LOKMAT SAMACHAR DT: 6/5/17

इंडोरामा ने दी महाराष्ट्र को 22 मेगावाट बिजली

बुटीबोरी कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट करेंगे: लोहिया

नागपुर, ५ मई (लोस सेवा).
इंडो रामा सिथेंटिक्स (इंडिया) लिमिटेड के सभापति व प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश लोहिया ने आज यहां कहा कि बुटोबोरी स्थित कंपनी के कैप्टिव पावर प्लांट के कारण उनके पास जरूरत से अधिक बिजली (सरप्लस) है. यहां से महाराष्ट्र की जनता के लिए फिलहाल ४० मेगावाट बिजली की आपूर्ति करना संभव है. जबकि आज से २२ मेगावाट की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि लोहिया समूह बिजली संकट को देखते हुए आने वाले वर्षों में अपने नए कारोबार के रूप में बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहल कर सकता है. इसके लिए आवश्यक अध्ययन किया जा रहा है. देश में बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए इस क्षेत्र में जाने की सोच मजबूत होती जा रही है. श्री लोहिया अपने बुटीबोरी स्थित दूसरे संयंत्र के औपचारिक उद्घाटन के लिए आज यहां आए थे. इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि वर्ष १९९२ में जब उन्होंने बुटीबोरी में इंडो रामा सिंथेटिक्स लिमिटेड के पहले संयंत्र की नींव रखी तो महाराष्ट्र में सरप्लस बिजली थी. बावजूद इसके भविष्य में इसकी कमी को भांपते हुए कंपनी ने अपना कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का बेहद भविष्यदर्शी निर्णय लिया. आज उसी का नतीजा है कि कंपनी के पास ८२ मेगावाट क्षमता का कैप्टिव पावर प्लांट है. इसमें से हमें केवल ४० मेगावाट बिजली की ही फिलहाल जरूरत है. बाकी बिजली हम राज्य का अंधेरा दूर करने के लिए देने को राजी है. लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार की उदासीनता के चलते बिजली आपूर्ति करार को अंतिम रूप लेने में काफी विलंब हुआ. यदि इस बाबत तत्परता से काम लिया जाता तो कंपनी २२ मेगावाट बिजली आज से तीन माह पहले ही महाराष्ट्र की जनता को उपलब्ध

शेष पृष्ठ १७ पर

इंडो रामा ने दी महाराष्ट्र को.....

करा चुकी होती है. खैर देर आयद दुरूस्त आयद आज शनिवार से कंपनी के बुटीबोरी स्थित कैप्टिव पावर प्लांट से स्टेट ग्रिड की मार्फत बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हो गई है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ६ रुपए प्रति यूनिट की दर से यह बिजली दी जा रही है. कुछ नए उपकरण स्थापित करने के बाद ही आपूर्ति क्षमता ४० मेगावाट तक हो जाएगी. अत: बिजली उपलब्ध कराने में कंपनी के योगदान में शीघ्र ही वृद्धि होगी. उन्होंने साथ ही बताया कि यहां बिजली उत्पादन क्षमता को करीब १०० मेगावाट तक बढ़ाने के लिए शीघ्र ही १५ मेगावाट का नया संयंत्र लगाया जाने वाला है. इसे करीब सवा साल की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पंजाब और गुजरात के कपास किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता अच्छी है. उन्हें दाम भी अच्छे मिल रहे है. अत: विदर्भ के कपास किसानों की बेहतरी के लिए सार्थक प्रयास किया जाना जरूरी है. क्योंकि विदर्भ के कपास किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं से उन्हें भी काफी तकलीफ पहुंच रही है. चूंकि इस क्षेत्र से उनका यहां स्थापित औद्योगिक ईकाई के नाते ही नहीं बल्कि नागपुर में ससुराल होने के नाते भी आत्मीय लगाव है. अत: इन आत्महत्याओं को लेकर उनसे भी देश के अन्य हिस्सों में जाने पर संबंधित लोग कुछ जानने की लालसा रखते है. इसलिए इस बाबत गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है. इन किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने के साथ ही वैज्ञानिक ढंग की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की मदद जरूरी है. क्योंकि वह अकेले यह काम नहीं कर सकते. एक सवाल के जवाब में श्री लोहिया ने कहा कि यदि इसके लिए कार्पोरेट फॉर्मिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी तो अवश्य जाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि विदर्भ के कपास उत्पादकों की बेहतरी के लिए वित्तीय और अन्य मदद मुहैया की जाएगी तो वह अवश्य इस कार्य में अपना पूरा सहयोग देंगे. इसके लिए अगले पखवाड़े दिल्ली जाकर संबंधितों के साथ मिल बैठकर चर्चा की जाएगी. नागपुर में टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना के लिए योगदान देने संबंधी सवाल के जवाब में श्री लोहिया का साफ कहना था कि ४० करोड़ की सब्सिडी लेकर महज टेक्सटाइल्स पार्क का निर्माण कर लेना काफी नहीं है. यहां टेक्सटाइल्स कंपनियों का आना जरूरी है. केंद्र की कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने टेक्सटाइल्स पार्क के लिए बड़े आकर्षक पैकेजों की घोषणा कर रखी है. अत: देश की टेक्सटाइल्स कंपनियां वहां अपने लिए ज्यादा संभावनाएं देख रही है. हालांकि हम सब मिलकर यहां भी पार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे. एक सवाल के जवाब में उनका स्पष्ट कहना था कि केवल सब्सिडी से टेक्सटाइल्स पार्क को अस्तित्व में लाना मुमकिन नहीं है. सब्सिडी पर निर्भर रहने से काम नहीं बनता है. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में टेक्सटाइल्स का एशिया का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) बन रहा है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखकर वह महाराष्ट्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने का मकसद रखते हैं. इसमें सबसे बड़ी बाधा परियोजनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक मंजूरियों के लिए उठानी पड़ती है. भीषण ऊर्जा संकट के बावजूद बुटीबोरी से राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए संबंधितों ने मंजूरी देने में इतना विलंब लगा दिया तो समझ सकते है कि बिजली घर के बाबत कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.